general approach is that environmental degradation results from the wide global disparities in patterns of consumption and production. In developing countries, economic and social development is a necessary pre-requisite for environmental protection. The international agenda should simultaneously address issues of environment and development and should focus adquately on environmental problems of specific relevance to developing countries. A meaningful programme of international cooperation should be based on provision of adequate, new and additional financial resources for developing countries and transfer of technology to them on a non-commercial or preferential basis.

मास्को में हुई पश्चिम शान्ति वार्ता

4393. **श्री अजीत जोगी:**
श्री छोटूभाई पटेल:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में मास्को में हुई पश्चिम शान्ति वार्ता में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो भारत ने इस वार्ता में क्या भूमिका निभाई?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अन्य देशों को दिए गए ऋण

4394. **श्री अजीत जोगी:**
श्री छोटू भाई पटेल:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा दक्षिण एशिया के अन्य देशों को दिए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 31 दिसम्बर, 1991 की स्थिति के अनुसार ऋण लेने वाले देशों को कुल कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई तथा उन्होंने कितनी ऋण राशि लौटाई;

(ग) क्या ये ऋण उन देशों की विशेष परियोजनाओं के लिए थे; और

(घ) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी): (क) और (ख) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है जिसमें यह सूचना दी गई है। [**नीचे देखिए**]

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सरकार द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान दक्षिण एशिया के देशों को दिए गए ऋण, वितरित की गई राशि और संबंधित देशों द्वारा 31 दिसम्बर, 1991 तक पुनर्भुगतान की गई राशि का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:—

वर्ष	दिया गया ऋण	वितरित की गई राशि	पुनर्भुगतान की गई राशि
नेपाल			
1989-90	5 करोड़ रुपये	5 करोड़ रुपये	5 करोड़ रुपये
1990-91	39 करोड़ रुपये	39 करोड़ रुपये	39 करोड़ रुपये
1991-92 (31.12.91 तक)	55 करोड़ रुपये	55 करोड़ रुपये	55 करोड़ रुपये
कुल :	99 करोड़ रुपये	99 करोड़ रुपये	99 करोड़ रुपये

यह भारत और नेपाल के बीच परिक्रामी ऋण करार के अनुसार था।

श्रीलंका

1987 के ऋण करार के अन्तर्गत श्रीलंका को 25 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। 31.12.91 की स्थिति के अनुसार श्रीलंका को 4.46 करोड़ रुपये की वास्तविक राशि वितरित की गई थी और कोई पुनर्भुगतान नहीं किया गया था।

बंगला देश

भारत से पूंजीगत वस्तुओं तथा मशीनरी के आयात के लिए 1991 के करार के द्वारा बंगलादेश को 30